फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 224 फरवरी 2007

सहकर्मियों–पड़ोसियों–सहयात्रियों के साथ प्रेम–आदर के रिश्ते बनाना वर्तमान व्यवस्था से पार पाने के लिये प्राथमिक आवश्यकताओं में है।

मजदूरों को दिखाना ही नहीं (6)

गुत्थी उत्पादन छिपाने की..... चोरी में चोरी

✱ कभी-कभार के शोषण की बजाय नियमित शोषण ऊँच-नीच, अमीरी-गरीबी वाली समाज व्यवस्थाओं का आधार होता है। नियमित शोषण के लिये शोषण-तन्त्र आवश्यक होते हैं। और चूँकि शोषितों द्वारा शोषण का विरोध स्वाभाविक है, किसी भी शोषण-तन्त्र को नियमित दमन की आवश्यकता होती है। शास्त्र और शस्त्र की जुगलबन्दी के संग पृथ्वी पर दमन-तन्त्रों का श्रीगणेश हुआ। दमन-तन्त्र का ही दूसरा नाम, अधिक प्रचलित नाम सरकार है। ✱ दमन-तन्त्र की विशेषता यह है कि यह खर्चा माँगता है। सरकार के खर्च का आदि-स्रोत टैक्स है और हाथ उत्पादन के आदि-स्रोत, इसीलिये कर = हाथ, कर = टैक्स। अधिक समय नहीं हुआ, महलों-किलों में रहने वाले राजा-सामन्त सरकार थे और भूदासों से उपज का छठा हिस्सा ($16^{2}/_{3}$%) वसूलने का कानून था। आज विधायक-सांसद-अधिकारी वाली सरकार के खर्च की पूर्ति के लिये कुल उत्पादन व खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा लिया जाता है। सरकारों द्वारा उपज-खपत का लगभग 70 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के टैक्सों के रूप में वसूलने के कानून हैं। ✱ भूदासों द्वारा अपनी उपज का $83^{1}/_{3}$% रखना कानून अनुसार था। उत्पादकता में छलाँगें लगी हैं और आज मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका एक-दो प्रतिशत मजदूरों के हिस्से में आना कानून अनुसार है। बाकी के 98 प्रतिशत में शोषण-तन्त्र और दमन-तन्त्र में हिस्सा-बाँट होती है। ✱ कानूनी और गैर-कानूनी में चोली-दामन का साथ रहा है। प्रहरी, कोतवाल, मन्त्री द्वारा रिश्वत लेने के किस्से बहुत पुराने हैं। दरअसल दमन-तन्त्र रिश्वत की चर्बी के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिये नगर-प्रान्त-देश के दायरों में कैद हो कर भ्रष्टाचार आदि को मूल समस्या मानना नादानी के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, गैर-कानूनी को मर्ज और कानून को दवा पेश कर कानून अनुसार दमन-शोषण को छिपाने का नुस्खा पुराना है, यह शुद्ध काँइयापन है। ✱ आज नई बात दमन-तन्त्र के संग-संग शोषण-तन्त्र में भी कानूनों का उल्लंघन, गैर-कानूनी कार्यों का बहुत-ही बड़े पैमाने पर होने लगना है। मण्डी-मुद्रा के साम्राज्य में कानूनों का यह अर्थहीन होना राजाओं-सामन्तों के अन्तिम चरण में कानूनों के अर्थहीन होने जैसा लगता है। *दिल्ली और इसे घेरे नोएडा, सोनीपत, बहादुरगढ, गुड़गाँव, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में कार्य करते 70-75 प्रतिशत मजदूरों को अब दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं को विलाप की वस्तु की बजाय नई सम्भावनाओं से ओत-प्रोत के तौर पर देखना बनता है।*

मण्डी-मुद्रा की गतिक्रिया के चलते कानूनी/गैर-कानूनी में हुई इस उलट-फेर के सन्दर्भ में यहाँ हम इन दो सौ वर्षों के दौरान मालिकाने में आये परिवर्तनों पर चर्चा जारी रखेंगे।

○कारखाने की स्थापना-संचालन की लागत में लगातार वृद्धि ने फैक्ट्री मालिक को एक आना-दो आना-चार आना वाले हिस्सेदार में बदला। फिर, लागत के बढते जाने के संग चन्द लोगों द्वारा मिल कर फैक्ट्री की स्थापना-संचालन असम्भव बना। हजारों शेयरहोल्डरों की भागीदारी वाले विशाल कारखाने उभरे जिनके संचालकों का लागत में अंश बहुत कम था। मालिक से हिस्सेदार बनने की राह ने प्रवर्तक-प्रमोटर बना दिया।

○कारखानों द्वारा विशाल आकार अख्तियार करने की अनिवार्यता ने हजारों शेयरहोल्डरों को जरूरी बनाया तो इनकी स्थापना-संचालन के लिये निदेशकों वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आवश्यक बने। "मालिक" शब्द-मात्र रह गया और प्रवर्तक लोग निदेशक मण्डल के तहत अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक बने। संचालन और मालिकाने में बहुत फर्क आ गया।

○प्रवर्तक/अध्यक्ष-प्रबन्ध निदेशक की असल स्थिति बहुत कमजोर बनी। कम्पनियों की मैनेजमेन्टें बदलना सामान्य बनने लगा। "मालिक नहीं, पर फिर भी मालिक" वाली स्थिति की नाजुकता बढी। बने रहने के लिये समर्थन की जुगाड़ ने, छिटक दिये जाने पर औकात बनाये रखने की चाहत ने चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर को कम्पनी की चोरी की राह पर अग्रसर किया।

○मण्डी-मुद्रा की गतिक्रिया विशाल-विराट कारखानों पर समाप्त नहीं होती। इस्पात कारखाने की बात करें तो स्टील उत्पादन में कोयला खदानें, चूना पत्थर खदानें, बिजलीघर, रेलवे जुड़ते जाते हैं। एक कारखाना कई अन्य कारखानों आदि की लड़ी की अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न करता है। इस सब से लागत इतनी बढ जाती है कि यह हजारों शेयरहोल्डरों के बूते से बाहर की चीज हो जाती है। मण्डी का खप्पर करोड़ों लोगों से अंश की माँग करता है, लेने लगता है। आज से 80-100 साल पहले यह हालात अस्तित्व में आ गये थे। और, इस सन्दर्भ में सरकारों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप एक बढती अनिवार्यता के तौर पर उभरा।

○करोड़ों लोगों के अंश लेने का प्रमुख माध्यम कर्ज बना। कम्पनी की स्थापना-संचालन की लागत के बढते हिस्से ने कर्ज का रूप लिया। जमीन गिरवी, इमारतें गिरवी, मशीनें गिरवी.... यह किसी अलग-थलग फैक्ट्री/कम्पनी की बातें नहीं हैं बल्कि वर्तमान में यह उत्पादन/वितरण क्षेत्र में सामान्य हालात हैं। आज कम्पनी स्थापना-संचालन की लागत का औसतन 15 प्रतिशत शेयरों से और 85 प्रतिशत कर्ज से आता है। संचालन और मालिकाने के बीच खाई बहुत चौड़ी हो गई है। फिर भी प्रवर्तक, शेयरहोल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर कम्पनियों की स्थापना-संचालन में उल्लेखनीय बने रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों ने किसी के कम्पनी का अध्यक्ष-प्रबन्ध निदेशक बने रहने के लिये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा शेयरहोल्डरों को साधने के संग-संग कर्ज देने वाली संस्थाओं के साहबों को साधे रखना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में "मालिक नहीं, पर फिर भी मालिक" की त्रासद स्थिति का एक और उदाहरण मात्र है कोरिया में नेताओं को रिश्वत देने के लिये विशाल हुन्दई कम्पनी के चेयरमैन को तीन वर्ष जेल की सजा।

○बैंक कर्ज के मुख्य स्रोत रहे हैं। पेन्शन फण्डों के बढते आकार ने उन्हें कर्ज देने वाले बड़े खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। अनेकों अन्य वित्त संस्थायें विशाल कर्ज देने वालों की कतारों में हैं। देशों के दायरों को तोड़ कर कर्ज विश्व स्तर पर दिया-लिया जाता है। एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी पर कब्जा करने में कर्ज देने वालों की भूमिका प्रमुख होती है। जिसकी पीठ पर कर्ज देने वाले अधिक शक्तिशाली गठबन्धन का हाथ होता है वही कब्जा करने में सफल होता-होती है। (बाकी पेज चार पर)

दर्पण में चेहरा-दर-चेहरा

चेहरे डरावने हैं.... आईना ही नहीं देखें या फिर हालात बदलने के प्रयास करें?

नूकेम केमिकल डिविजन मजदूर : "54 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में कम्पनी 6 तारीख को नोटिस लगा देती थी कि तनखा 16-20 को देगी। सूचना टाँगने के बाद मैनेजमेन्ट इस बारे में फिर बात ही नहीं करती थी। कम्पनी स्वयं द्वारा निर्धारित तारीख निकलने के बाद भी तनखा नहीं देती थी। हम मजदूरों द्वारा कहा-सुनी पर 22-24 तारीख को वेतन दिया जाता था। इस सिलसिले में नवम्बर 06 की तनखा हमें 29 दिसम्बर को जा कर दी गई। इधर दिसम्बर के वेतन के बारे में कम्पनी ने कोई सूचना नहीं टाँगी और आज 10 जनवरी तक तनखा दी भी नहीं है।"

लखानी इण्डिया वरकर : "प्लॉट 230 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में साबुन का उत्पादन 4 महीने बन्द रहने के बाद 1.11.06 से फिर आरम्भ हुआ है। कम्पनी ने स्वयं 40 मजदूर भर्ती किये हैं और 10 को ठेकेदार के जरिये रखा है। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की हैं। ओवर टाइम का भुगतान डबल की दर से नहीं बल्कि 15 रुपये प्रति घण्टा के हिसाब से किया जाता है। डिटरजेन्ट साबुन के उत्पादन में हाथ-पैर छिल जाते हैं और आँख में गिर जाने पर भारी परेशानी होती है।"

शिवालिक ग्लोबल मजदूर : "12/6 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में तनखा 2000 रुपये है पर ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि 2485 के हिसाब से काटते हैं – इन 2000 रुपयों में से ही काटते हैं। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की हैं। ओवर टाइम के पैसे तनखा वाले 2000 के हिसाब से सिंगल रेट से तो देते ही हैं, इन में भी हर महीने 200-400 रुपये की गड़बड़ करते हैं। इधर 8-9 मजदूरों ने शिकायतें कर के यह 200-400 रुपये लिये हैं।"

इण्डिया फोर्ज वरकर : "28 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 50 स्थाई मजदूर और 25 ठेकेदारों के जरिये रखे 200 वरकर काम करते हैं। ठेकेदारों के जरिये रखों में हैल्परों की तनखा 1600-2000 रुपये और ऑपरेटरों की 2000-2100 रुपये तथा बहुत कम की ई.एस. आई. व पी.एफ.। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से और बहुत देरी से। तनखा 25-26 तारीख को जा कर। फैक्ट्री में पीने का पानी खारा है।"

स्काईटोन इलेक्ट्रीकल्स मजदूर : "42-43 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 50 स्थाई मजदूर और ठेकेदारों के जरिये रखे 250 वरकर काम करते हैं। ठेकेदारों के जरिये रखों की तनखा 2100-2200 रुपये है पर ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि 2484 रुपये पर काटते हैं। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से, 2100-2200 रुपये तनखा के हिसाब से। फैक्ट्री महीने के तीसों दिन चलती है – आधे मजदूर महीने के 2 रविवार को और आधे बाकी के दो रविवार को, पर हाँ, रविवार को ड्युटी 8-8 घण्टे। मजदूरों के जो पैसे कम्पनी-ठेकेदार के हिसाब से बनते हैं उन में से भी 250-500 रुपये हर महीने दिहाड़ियों में गड़बड़ी कर हड़प लिये जाते हैं।"

सुपर फैशन मजदूर : " 12/4 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में धागा काटने वाले मजदूरों को 8 घण्टे प्रतिदिन पर 30 दिन के 1800 रुपये देते हैं। सुबह 9½ से साँय 6¼ की शिफ्ट है पर रात 9 बजे तक तो रोकते ही रोकते हैं और फिर रात 2 बजे तक भी रोक लेते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। फैक्ट्री में काम करते 175 कैजुअल वरकरों की ई.एस. आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ठेकेदारों के जरिये रखे 350 मजदूरों में से कुछ की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं।"

एस पी एल इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 22 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों की तनखा 1800-2200 रुपये। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कैन्टीन में स्थाई मजदूरों को 10 रुपये में थाली और बाकी सब मजदूरों को 15 रुपये में थाली देते हैं।"

पदम इंजिनियरिंग मजदूर : " प्लॉट 162 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में काम करते 70 वरकरों में 7 स्थाई हैं और बाकी को 5 ठेकेदारों के जरिये रखा है। ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की तनखा 1800-2000 रुपये और ई. एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। फैक्ट्री में रोज 4 या 5 घण्टे ओवर टाइम करवाते हैं और इसका भुगतान सिंगल रेट से। तनखा देरी से – 20 तारीख के बाद। फैक्ट्री में एस्कोर्ट्स ट्रैक्टरों के पुर्जे बनते हैं।"

और, एस्कोर्ट्स महिमा

एस्कोर्ट्स मजदूर : "सैक्टर-13 स्थित फार्मट्रैक प्लान्ट में असेम्बली लाइन में दो शिफ्ट हैं और हीट ट्रीटमेन्ट तथा पेन्ट शॉप में तीन शिफ्ट। पेन्ट शॉप में 35 स्थाई मजदूर हैं, अधिकतर ए-शिफ्ट में हैं और बाकी बी-शिफ्ट में। सी-शिफ्ट में कैजुअल तथा ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर ही रहते हैं। पेन्ट शॉप में 35 कैजुअल और 4 ठेकेदारों के जरिये रखे 190 वरकर हैं। एस्कोर्ट्स फार्मट्रैक पेन्ट शॉप में 13-14% स्थाई मजदूर, 13-14% कैजुअल वरकर, और 72-74% ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर काम करते हैं।

" एक ठेकेदार के जरिये रखे पेन्ट तैयार करने वाले वरकर सफाई भी करते हैं – एक शिफ्ट में 4 बार पोंचा लगाते हैं, पहले थिन्नर से और फिर पानी से। इन मजदूरों को 8 घण्टे के 90 रुपये देते हैं, ई.एस.आई. कार्ड तथा गुड़गाँव के नम्बर वाली पी.एफ. स्लिप दी हैं। पेन्ट शॉप के बड़े ठेकेदार, जैन ग्लोबल से मजदूरों को भारी दिक्कतें हैं। आठ घण्टे के लिये स्प्रे पेन्ट करते 40 मजदूरों को 180 रुपये, पेन्ट के लिये लाइन पर माल चढ़ाते व उतारते 40 मजदूरों में से 20 को 164 रुपये और 20 को 125 रुपयें, सी-शिफ्ट में सी डी में काम करते 12 मजदूरों को 96 रुपये। जबकि, ***एस्कोर्ट्स कम्पनी 8 घण्टे प्रति पेन्टर के 256*** रुपये ठेकेदार को देती है। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से।

" जैन ग्लोबल ने फोटो सब मजदूरों से ली हैं पर ई.एस.आई. कार्ड आधों को ही दिये हैं और पी.एफ. में तो घोटाला नजर आता है। ठेकेदार कम्पनी का मैनेजर कहता है कि पी. एफ. गुजरात में जमा हो रहा है। मामूली गलती पर एक पेन्टर को 5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया परन्तु भविष्य निधि राशि निकालने का फार्म भर कर नहीं दे रहे। जैन ग्लोबल का मैनेजर कहता है कि फार्म भरने के लिये समय नहीं है, 4-5 बार ऐसा कह चुका है। रात की ड्युटी वालों ने पेन्ट कनवेयर सुबह 7½ बजे बन्द की तो ठेकेदार कम्पनी का मैनेजर बोला कि 8 बजे तक चलाओ। मजदूरों द्वारा इनकार करने पर साहब ने 2-3 का गला पकड़ा। ऐसे नौकरी नहीं करनी कह कर 5 मजदूरों ने नौकरी छोड़ दी। यह दो महीने पहले की बात है और उन 5 मजदूरों के पी. एफ. राशि निकालने के फार्म भी जैन ग्लोबल नहीं भर रही – साहब कहता है कि तनखा दे दी वही बहुत है, फार्म नहीं भरेंगे।

"और, एस्कोर्ट्स फार्मट्रैक में ***हरियाणा वेलफेयर फण्ड के नाम पर हर मजदूर की तनखा में से हर महीने ठेकेदार 80-90 रुपये काट लेते हैं।*** हरियाणा वेलफेयर फण्ड के नाम पर ही जी.ई. मोटर्स में प्रत्येक मजदूर की तनखा में से एक रुपया हर माह काटते हैं।

"ठेकेदार को पेन्टर की दिहाड़ी 256 रुपये देती एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट स्वयं भी पेन्टरों को कैजुअल वरकरों के तौर पर भर्ती करती है। इन कैजुअल पेन्टरों में आधों की दिहाड़ी 164 रुपये और आधों की 125 रुपये है। पेन्ट शॉप में स्थाई मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपये। पेन्ट शॉप में एक समान काम करते मजदूरों की दिहाड़ी 96,125,164,180,600 रुपये हैं। एस्कोर्ट्स फार्मट्रैक के अन्य विभागों में कैजुअलों में हैल्परों की दिहाड़ी 105 रुपये और फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट आदि कारीगरों में कुछ की दिहाड़ी 125 रुपये तथा कुछ की 145 रुपये। सब विभागों में स्थाई मजदूरों की दिहाड़ी 600 रुपये के आसपास।

"कैन्टीन में कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को भारी दिक्कत होती है। ए और बी शिफ्ट में 3-3 लाइनें लगती हैं तथा एक पंक्ति में 100 से ऊपर लोग होते हैं। भोजन अवकाश आधे घण्टे का – खाना लेने में ही आधा घण्टा लग जाता है।"

पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी फरीदाबाद – 121001

बमों द्वारा सुरक्षा

मार्च 05 में अमरीका के टेक्सास प्रान्त में एक परमाणु बम लगभग फट गया था। यह बम जापान में हीरोशिमा नगर पर 1945 में गिराये एटम बम से सौ गुणा शक्तिशाली था। बाल-बाल टले इस महाविनाश के तथ्य को गुप्त रखा गया। बीस महीने बाद, फैक्ट्री में सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में नवम्बर 06 में अमरीका सरकार ने परमाणु बम निर्माण करने वाली कम्पनी, बी डब्लू एक्स टेक्नोलोजीज पर 50 लाख रुपये का जुर्माना किया तब भयावह हालात की थोड़ी-सी जानकारी सामने आई है। परमाणु बमों के निर्माण वाली फैक्ट्री में काम करते तकनीकी वरकरों ने कार्य की खराब स्थितियों को लगभग हो गये विस्फोट के लिये जिम्मेदार ठहराया है। परमाणु बम बनाने वाली फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 से 16 घण्टे कार्य करना अनिवार्य है, सप्ताह में 72-84 घण्टे एटम बम बनाने में खटना ! अधिक बुरी सूचना यह है कि कम्पनी ने 2007 के लिये परमाणु बमों के उत्पादन के लक्ष्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। (जानकारी फरवरी 07 की "सोशलिस्ट स्टैन्डर्ड" पत्रिका से, जिसने इसे 18 दिसम्बर 06 के "दि नेशन" से लिया। पता : Socialist Standrad, 52 Clapham High Street, London SW4 7UN, Great Britain)

रूस में चेरनोबिल परमाणु बिजलीघर द्वारा मचाई विनाशलीला को अधिक समय नहीं हुआ है। भारत सरकार के एटम बम बनाने वाले कारखानों और परमाणु बिजलीघरों में कार्यस्थितियाँ तथा सुरक्षा के उपाय अमरीका सरकार, रूस सरकार के ऐसे संस्थानों से बदतर ही हैं।

दिल्ली से – *अब दिल्ली में 8 घण्टे की ड्युटी और हफ्ते में एक छुट्टी पर कम से कम तनखा हैल्पर की 3312 रुपये (8 घण्टे के 127 रुपये 40 पैसे); अर्ध-कुशल श्रमिक की 3478 रुपये (8 घण्टे के 133 रुपये 80 पैसे); कारीगर की 3736 रुपये (8 घण्टे के 143 रुपये 70 पैसे)। स्टाफ में कम से कम तनखा अब मैट्रिक से कम की 3505 रुपये; मैट्रिक पास परन्तु स्नातक से कम की 3760 रुपये; स्नातक एवं अधिक की 4072 रुपये।*

ओबराय इन्डस्ट्रीज मजदूर : " डी डी ए शेड नं. 32 स्कीम 3 ओखला फेज 2 स्थित फैक्ट्री में वैल्डिंग का काम होता है। हैल्परों की तनखा 1800-2000 रुपये और कारीगरों की 3000-3500 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

नूतन प्रिन्टिंग प्रेस वरकर : " एफ 89/12 ओखला फेज 1 स्थित फैक्ट्री में 5 ऑपरेटर तथा 20 हैल्पर काम करते हैं। हैल्परों को 12 घण्टे रोज पर महीने के 2500 रुपये देते हैं। ऑपरेटरों की तनखा 4000 रुपये है और ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। हैल्परों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

परफैक्ट इम्ब्राइड्री मजदूर : "बी-140 ओखला फेज 1 स्थित फैक्ट्री में सिलाई के हैल्परों की तनखा 2000 रुपये और कारीगरों की 3800-4000 रुपये तथा ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। इम्ब्राइड्री के हैल्परों को 12 घण्टे रोज पर महीने के 1800 रुपये और ऑपरेटरों को ऐसे में 3000-3600 रुपये। फैक्ट्री में किसी मजदूर की ई.एस.आई.व पी.एफ. नहीं हैं। माल कई महीने स्टोर में पड़ा रहता है परन्तु मशीन पर आते हीं अरजेन्ट हो जाता है और सुपरवाइजर चिल्लाने लगता है। एक दिन की छुट्टी करने पर मजदूर को 10-12 दिन बाहर कर देते हैं। मैडम गाली दे कर बात करती है और छोटी-सी बात पर हाथ उठा देती है। दिसम्बर की तनखा 25 जनवरी को जा कर दी।"

कॉन्टीनेन्टल क्राउन वरकर : " डी डी ए शेड बी-154 ओखला फेज 1 स्थित फैक्ट्री में काम करते 60 मजदूरों में 16 स्थाई हैं। कैजुअलों में पुरानों को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं परन्तु बाकी की तनखा 1800-2100 रुपये है और उनकी ई. एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर-हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी और महीने में 4 छुट्टी पर जुलाई 06 से 2484 रुपये 28 पैसे है, 8 घण्टे काम के लिये 95 रुपये 55 पैसे। जनवरी 07 से देय डी. ए. फरवरी के आरम्भ तक हरियाणा सरकार ने घोषित नहीं किया था।

सुपर पोलीमर मजदूर : "17-सी इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। बहुत-ही गन्दा काम है, रबड़ की शीट बनती हैं और सिर्फ एक एग्जास्ट पँखा है।"

नेफा एक्सपोर्ट मजदूर : "29 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12½ घण्टे की एक शिफ्ट है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

झालानी इम्पैक्स मजदूर : "21 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 12½ घण्टे की एक शिफ्ट है और रात-भर भी रोक लेते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से।"

सुपर फैशन वरकर : "प्लॉट 262 ए-बी सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

एयर बूस्ट ओवरसीज मजदूर : "27/62 लक्ष्मी रतन कम्पलैक्स, इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1600-1800 रुपये और ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। सुबह 8½ से सायँ 5 की शिफ्ट है पर 7 बजे तक तो रोकते ही हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। यहाँ सीमेन्ट फैक्ट्रियों के लिये एयर ब्लास्टर बनते हैं।"

जे बी एम वरकर : "268 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे 400 मजदूरों में हैल्परों की तनखा 2100 रुपये। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से।"

बन्दी वाणी (12)

अमरीका सरकार ने "अपने" बीस लाख लोगों को सजा दे कर और आठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप में बन्दी बना रखा है। यूँ तो सम्पूर्ण संसार ही जेलखाने में ढाल दिया गया है, अधिकाधिक ढाला जा रहा है, फिर भी, सरकारों के कारागारों में बन्द हमारे बन्धुओं पर जकड़ हम से अधिक होती है। अमरीका में कैलिफोर्निया प्रान्त की एक जेल में बन्द गैरी हॉलफोर्ड के और पत्र इधर हमें मिले हैं।

सामान्य तौर पर प्रत्येक को अनेक खाकों-खानों-आल्ओं में रखे जाने से मैं बहुत विस्मित हूँ। कभी-कभार ही कोई आपके साथ समान के तौर पर व्यवहार करता-करती है। आमतौर पर मनमर्जी से कोई भिन्नता ढूँढ ली जाती है और उसी के अनुसार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है। खानों-खाकों-आल्ओं की सूची अनन्त है : आयु, लिंग, चमड़ी का रंग, धर्म-सम्प्रदाय, राष्ट्रीयता, राजनीतिक झुकाव, कद, वजन, बालों का रंग.....

व्यक्ति को खानों-खाकों-आल्ओं में रखने का व्यक्ति-विशेष से कुछ लेना-देना नहीं होता। बल्कि, दमन करने अथवा डराने-धमकाने के लिये किसी मनमर्जी की भिन्नता का इस्तेमाल कर व्यक्ति को खानों-खाकों-आल्ओं में रखा जाता है। अदृश्य शक्तियाँ जो कि अधिकतर "स्वतन्त्र लोगों" के ध्यान में नहीं आती, उन अदृश्य शक्तियों द्वारा पूरे दिन और प्रतिदिन ऐसा किया जाना एक कैदी के नाते मैं देखता हूँ। अमरीका सरकार के जेलखानों में रंगभेद छाया हुआ है और कट्टर ईसाई तथा मुसलमान तो गिरोहों वाली मनःस्थिति में पहुँच गये हैं। अगर आप मूसा-ईसा-मोहम्मद वाले धर्मों को स्वीकार नहीं करते तो आप को साथी बन्दी व जेल प्रशासन ही नहीं बल्कि धर्म अधिकारी भी अचम्भित करने वाली हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में जेल में निवास स्थान ढूँढना असम्भव-सा हो जाता है। प्रत्येक जायज माँग-प्रयास में अड़ँगा डाला जाता है, देरी की जाती है, अनदेखा किया जाता है, इन्कार किया जाता है। इस सब के खिलाफ अमरीका सरकार के न्यायालयों में मामले दायर करने वाले कैदियों को अदालतें शत्रु के तौर पर लेती हैं। हालात भद्दे-बहूदे हैं....(गैरी को अँग्रेजी में इस पते पर लिख सकते हैं :

– Gary Hallford, T-58516, C.S.P.-Solano, 17-211L, P.O.Box 4000, Vacaville, CA 95696-4000, U.S.A.

मृत्यु पर नाम गायब

नित्या एक्सपोर्ट मजदूर : "बडकल चौक के निकट मथुरा रोड़ पर स्थित फैक्ट्री के गेट पर स्कोर्पियो एपरेल्स का नाम लिखा है पर यह नित्या एक्सपोर्ट के नाम से जानी जाती है। कम्पनी की दिल्ली और फरीदाबाद स्थित तीन फैक्ट्रियों में 2500 मजदूर काम करते हैं जिनमें बड़ी सँख्या महिला मजदूरों की है।

"नित्या एक्सपोर्ट में सुबह 9 से रात 8 बजे तक की शिफ्ट है परन्तु पुरुष मजदूरों को उसके बाद भी रोक लेते हैं। इस प्रकार रात 8 बजे बाद रोके गये मजदूर 12 जनवरी को देर रात फैक्ट्री से छूटने पर मथुरा रोड़ पर वाहन की चपेट में आ गये। एक मजदूर की मृत्यु हो गई। ***नित्या एक्सपोर्ट (स्कोर्पियो एपरेल्स) कम्पनी ने मृत मजदूर का नाम फैक्ट्री के दस्तावेजों से गायब कर दिया और लाश को पहचानने से इनकार कर दिया।*** पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों ने अपनी स्वाभाविक भूमिका निभाई।

"इधर नित्या एक्सपोर्ट के किसी मजदूर की एक कविता फैक्ट्री में घूम रही है :

सुन लो सजन
कुछ ऐसी सुनाता हूँ
नित्या का अपना कमाल
देश की शासन व्यवस्था को
ठेंगा दिखाये बेमिसाल।
वरकर बेचारे नाइट करें
लाइफ से अपनी, वो फाइट करें
वापस में जब वो सड़क पे मरें
तो कर दें रिकार्ड से
नौकरी हलाल।
पुलिस हमारी भी, क्या करे?
मुँह बन्द जानवर हैं अन्दर भरे
आँखें तरेर उन पे चमचे खड़े
ज़बान हिलते ही होगी बवाल।
लेबर कमिश्नर भी आये टपक
पूछा न कुछ, लिया रुपया लपक
रोते रहे दिल अन्दर फफक
लेकिन चलते रहे वो दलाल।
इनसान यदि यहाँ जाता है मर
ऐसी खबर कोई लिखता अगर
कविता बता के हँसें जानवर
मौत का भी नहीं है मलाल।
शक्ति है नारी में देवी समान
कहता दुशासन पकड़ने को कान
इज्जत परायी ना समझे नादान
बुद्धि है विपरित.... विनाशकाल।"

मजदूरों को दिखाना ही नहीं .....

(पेज एक का शेष)

कोरेस स्टील पर टाटा स्टील का कब्जा टाटा स्टील अथवा रतन टाटा की शक्ति का परिणाम नहीं है। बल्कि, यह टाटा स्टील को कर्ज देने वाले गठबन्धन का प्रतिद्वंद्वी ब्राजील में मुख्यालय वाली कम्पनी को कर्ज देने वाले गठबन्धन से अधिक शक्तिशाली होने का नतीजा है। (जारी)

विचारणीय

भाषा की राजनीति

उपमहाद्वीप के छुट-पुट क्षेत्रों में समुदायों का टूटना मिश्र-इराक-चीन में ऐसा होने जितना ही प्राचीन है। समुदायों की टूटन मानवों में ऊँच-नीच लाई। प्रारम्भ में ऊँच-नीच स्वामी और दास के रूप में थी। स्वामियों के आचार-विचार को भारतीय सभ्यता कहा जाता है, भारतीय सभ्यता का आदि-स्रोत कहा जाता है। इसी प्रकार मिश्र-इराक-चीन-यूनान-रोम में स्वामियों के आचार-विचार को चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता आदि कहा जाता है। यूनान व रोम के स्वामियों के आचार-विचार को यूरोपीय अथवा पश्चिमी सभ्यता, उसके आदि-स्रोत भी कहा जाता है।

मानवों के बीच की मामूली-मामूली भिन्नतायें समुदाय में बहुआयामी सम्बन्धों की सुगन्ध लिये होती हैं। ऊँच-नीच वाले सामाजिक गठन में मामूली भेद को बढा-चढा कर प्रस्तुत किया जाता है और थोड़े-से फर्क को बढाने के लिये अनेकानेक प्रपंच किये जाते हैं। स्वामियों ने दासों की भाषाओं से अलग भाषा अपने लिये गढी। स्वामियों की उपमहाद्वीप में प्रमुख भाषा संस्कृत थी और दासों के संस्कृत सीखने-बोलने पर कठोर-क्रूर पाबन्दियाँ थी।

आज के और निकट आयें तो उपमहाद्वीप में बेगार-प्रथा पर पलते तबके ने रैयत की बोली-भाषाओं से अलग फारसी को अपनी भाषा बनाया। और, मण्डी-मुद्रा का फैलाव उपमहाद्वीप में अँग्रेजी लाया...

लूट-खसूट में पुराने-नये "उपमहाद्वीप वाले" हिस्सेदारों के प्रमुख हिस्सों ने अपनी हिस्सेदारी बढाने के लिये अँग्रेजी सीखने के संग-संग उर्दू-हिन्दुस्तानी-हिन्दी के झण्डे लहराये। सफलता हासिल करने पर बनी पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राजभाषा घोषित किया जबकि क्षेत्र में अधिकतर लोग "बांग्ला", "पँजाबी", "सिरियांकी", "सिन्धी", "पश्तो" आदि भाषायें बोलते थे। भारत सरकार ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। जिसे हिन्दी क्षेत्र कहा जाता है उस की ही बात करें तो वहाँ हिन्दी की बजाय व्यापक स्तर पर तो अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुन्देली, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, गढवाली, कुमाउँनी, मगही, सन्थाली, निमाड़ी, मालवी आदि-आदि भाषा समूह ही पाये जाते थे और अभी भी उल्लेखनीय हैं।

जन सामान्य की भाषा-बोलियों को असभ्य/अपभ्रंश/गँवार और उर्दू-हिन्दी को तहजीब की भाषा, शुद्ध भाषा कहा गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार की उर्दू और भारत सरकार की हिन्दी का आगमन सौ वर्ष देरी से हुआ। इसलिये पाकिस्तान सरकार-भारत सरकार ने राजकाज के लिये अँग्रेजी को ही बनाये रखा तथा बढाया है। इसका एक कारण ऊँच-नीच जनित काँइयेपन में दीर्घ अनुभव भी लगता है – उर्दू/हिन्दी को मजदूरों-किसानों-दस्तकारों से पर्याप्त दूरी बनाने वाली नहीं पा कर उपमहाद्वीप में साहबों ने अँग्रेजी को अपना हथियार बनाये रखा है। और, मण्डी-मुद्रा के व्यापक प्रसार के दृष्टिगत साहब लोग अब तो खुलेआम कहते हैं कि मजदूर-मेहनतकश कामचलाऊ अँग्रेजी सीखें.... भारत सरकार के ज्ञान आयोग, यानि, नोलेज कमीशन ने सब विद्यालयों में पहली कक्षा से अँग्रेजी पढाने को कहा है।

ऊपर हम ने पँजाबी, सिन्धी आदि को उद्धरण चिन्हों में रखा है। यह इसलिये कि हिन्दी की ही तरह कई भाषाओं को छिपा कर-दबा कर सरकारी पँजाबी, मराठी, कन्नड, तमिल, उड़िया आदि की स्टैन्डर्ड भाषाओं के तौर पर रचना की गई है। और, कई प्रकार की डोगरी, काश्मीरी, लद्दाखी भाषाओं वाले क्षेत्र की राजभाषा उर्दू घोषित करना भाषा की राजनीति के टेढे पेंचों की एक अन्य झलक मात्र है।

भाषा की राजनीति इस उपमहाद्वीप की विशेषता नहीं है। अँग्रेजी जहाँ की भाषा कही जाती है वहाँ आइरिश, वैल्श, स्कॉटिश आदि भाषाओं का दमन किया गया। हालाँकि इंग्लैण्ड के राजा जर्मन भाषा बोलने वाले थे, मण्डी-मुद्रा वाली ऊँच-नीच की जरूरतों ने ब्रिटेन में अँग्रेजी भाषा को गढा व स्थापित किया। जिसे यहाँ उपमहाद्वीप में अँग्रेजी कहा जाता है उसकी रचना व पालन-पोषण ऑक्सफोर्ड-कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में हुआ है और यह ब्रिटेन में साहबों की भाषा है। इसी प्रकार जिसे फ्राँसिसी भाषा कहा जाता है उसकी रचना हुई है। अनेक भाषाओं का दमन कर मण्डी वाली ऊँच-नीच की जरूरत के अनुरूप इतालवी भाषा की रचना व स्थापना को इस सन्दर्भ में एक प्रतिनिधि उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं।

इस उपमहाद्वीप की ही तरह अफ्रीकी महाद्वीप में अँग्रेजी-फ्राँसिसी की और दक्षिण अमरीकी महाद्वीप में स्पेनी-पुर्तगाली भाषाओं की राजनीति है।

ऊँच-नीच वाले समाज में, बँटे हुये समाज में भाषा को आदान-प्रदान का माध्यम मानना नादानी है। अँग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, तेलुगु, मलयालम, असमी, सिन्धी, पश्तो आदि भाषायें उपमहाद्वीप में मजदूरों-मेहनतकशों के खिलाफ पहचान की राजनीति के एक औजार के तौर पर भी काम कर रही हैं। मण्डी हमें इस-उस भाषा को सीखने को मजबूर कर रही है। इसे एक मजबूरी के तौर पर लेना ही बनता है। यह हमारी मजबूरी है कि हम यह सब हिन्दी में कह रहे हैं।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।

RN 42233 *पोस्टल रजिस्ट्रेशन* **L/HR/FBD/73**